

(93)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1559-तीन/2009 - विरुद्ध आदेश
दिनांक 17-9-2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना
- प्रकरण कमांक 158/2006-07 अपील

नवल सिंह उर्फ सीताराम पुत्र सोनेराम
ग्राम खिरावली तहसील व जिला मुरैना
विरुद्ध

—आवेदक

1- रामस्वरूप पुत्र कोक सिंह गुर्जर
2- कोक सिंह पुत्र सोनेराम
ग्राम सिरवली तहसील मुरैना

—अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 14-9-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्र.क. 158/
2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-9-2009 के विरुद्ध मध्य प्रदेश
भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि स्व० ओछेलाल के नाम ग्राम खिरावली
में कुल कित्ता 4 कुल रकबा 5 वीघा 7 विसवा भूमि थी जिनकी मृत्यु उपरांत
राजस्व निरीक्षक मुरैना ने ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 6 पर

आदेश दिनांक 26-01-1998 से नवल सिंह एवं कोक सिंह का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 34/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-6-2001 से राजस्व निरीक्षक मुरैना का आदेश दिनांक 26-01-1998 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर आदेश पारित करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित हुआ। तहसील न्यायालय में प्रकरण आने पर क्रमांक 20 अ-6/2000-01 पर पेंजीबद्ध करते हुये नायब तहसीलदार मुरैना ने पक्षकारों की सुनवाई की। नायब तहसीलदार ने हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 5-1-2002 पारित किया तथा उक्तांकित भूमि के हिस्सा 1/2 भाग पर बसीयतग्रहीता रामस्वरूप का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 17/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-1-2007 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 158/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-9-2009 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने आदेश दिनांक 21-6-2001 से हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु तहसील न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया था, किन्तु नायब तहसीलदार ने आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित

अवसर नहीं दिया। नायव तहसीलदार ने प्राकृति न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करके आदेश दिनांक 5-1-2002 पारित किया है जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने एवं अपर आयुक्त ने ध्यान नहीं दिया है। आवेदक की साक्ष्य एवं सुनवाई तहसील न्यायालय में कराई जावे, जिससे आवेदक को न्याय मिल सके। उन्होंने तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने की मांग रखी।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 17-9-2009 में दिये गये विवरण के अवलोकन से पाया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आदेश में निम्नानुसार विवेचना कर निष्कर्ष निकाले है :-

“ नायव तहसीलदार ने अपीलार्थीगण की साक्ष्य लिये जाने हेतु पेशियों नियत की है और साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु बार-बार समय दिया, किन्तु अपीलार्थीगण ने नायव तहसीलदार के समक्ष लेखी/मौखिक साक्ष्य के कथन नहीं कराये। अपीलार्थीगण द्वारा नायव तहसीलदार के समक्ष व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 13 नियम -2 के आवेदन प्रस्तुत होने पर वरिष्ठ न्यायालय में निगरानी करने हेतु भी पर्याप्त अवसर दिया है किन्तु उन्होंने बचाव में न तो निगरानी की ओर से न ही लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत। अतः यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थीगण को सुनवाई का एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। ”

उक्त से यह समाधान हो जाता है कि नायव तहसीलदार न्यायालय में आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी मुरैना द्वारा आदेश दिनांक 21-6-2001 से मामला पक्षकारों की साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है एवं उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है अब मामला पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। नायव तहसीलदार मुरैना के आदेश

दिनांक 5-1-02 में , अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के आदेश दिनांक 22-1707 में तथा अपर आयुक्त, मुरैना संभाग के आदेश दिनांक 17-9-09 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 158/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-9-2009 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।


(एस एस शर्मा)
सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर